द्वितीय अध्याय

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

अध्याय द्वितीय

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

2.1 भूमिका :-

व्यावहारिक दृष्टि से सारा मानव ज्ञान पुस्तक एवं पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है, अन्य जीवों के अतिरिक्त जो प्रत्येक पीढ़ी में नये सिरे से प्रारंभ करते है। मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहित एवं सुरक्षित रखता है, ज्ञान के अथाह भंडार में मानव का निरन्तर योगदान सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है।''

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

साहित्य का पुनरावलोकन प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। साहित्य पुनरावलोकन एक कठिन परिश्रम का कार्य है। प्रत्येक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान में चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो अथवा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हो साहित्य का पुनरावलोकन तक अनिवार्य और प्रारंभिक कदम है। क्षेत्रीय अध्ययनों में जहाँ उपलब्ध उपकरणों तथा नवीन स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग तथा प्रदत्त संकलन का कार्य होता है। समस्या से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन अनुसंधान का प्राथमिक आधार तथा अनुसंधान के गुणात्मक स्तर के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है।

2.2 साहित्य के पुनरावलोकन से लाभ :-

(1) जो अनुसंधान कार्य पहले अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा किया

जा चुका है वह पुनः किया जा सकता है।

(2) ज्ञान के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवश्यक है अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञान हो कि ज्ञान की वर्तमान सीमा कहाँ पर है। वर्तमान ज्ञान की जानकारी के पश्चात् ही ज्ञान आगे बढ़ाया जा सकता है।

(3) पूर्व साहित्य के पुनारावलोकन से अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के विधान की रचना के संबंध में अर्न्तदृष्टि प्राप्त हो सकती है।

(4) पूर्व अनुसंधानों के अध्ययन से अन्य संबंधित नवीन समस्याओं का पता लगता है।

(5) सत्यापन करने के लिए कुछ अनुसंधानों को नवीन दशाओं में करने की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार साहित्य के पुनरावलोकन का अनुसंधान में बहुत महत्व है। प्रस्तुत समस्या से संबंधित साहित्य का पुनारावलोकन इस प्रकार हैः-

2.3 संबंधित साहित्य :-

1. चीनारा बी, (1997). शिक्षा और जनतंत्र, नई दिल्ली.

यह पुस्तक जनतांत्रिक मूल्य से सम्बन्धित है। विद्यार्थियों को एन्स्ट्रक्शनल टेकनिक के द्वारा स्वतंत्रता स्वायतता, अपनी भव्यता के प्रति मान की ओर विषयाभिमुख करने के लिये वर्तमान शिक्षकों और भविष्य के शिक्षकों के आधारभूत सामग्री यह पुस्तक में हैं। जनतांत्रिक मूल्यों के सैद्धान्तिक सिद्धान्तों को इस विभाग में शामिल किया गया है। शिक्षा में जनतांत्रिक मूल्य की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में भी किताब में वर्णन है। रूपांतरित वेल्यू सर्वे कन्फ्रन्टेशन इंस्ट्रूमेन्ट और वेल्यू क्लेरिफाईग इंस्ट्रूमेन्ट हमको जनतंत्र मूल्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करता है और मूल्यों की उपयोगिता से अवगत कराता है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

2. गोस्वामी, पी.सी. (1987). जीवन, जनतंत्र और शिक्षा.

यह पुस्तक जीवन में जनतंत्र और शिक्षा से संबंधित है, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर पढ़ाने की पद्धति और शिक्षा की संरचना की चर्चा की गई है। जो महात्मा गांधीजी के मूलभूत शिक्षा के विचार पर आधारित है, उसमें जनतांत्रिक देश का आर्थिक विकास, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, शैक्षिक बेकारों की समस्या, राष्ट्रीय नीति और वैदिक युग में शिक्षा की प्रगति की बात की गई है।

3. झा, एस.एन. (1985). समाजवाद, असांप्रदायिकता और जनतंत्र, दिल्ली, अमर प्रकाशन.

शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य, समाजवाद, असाम्प्रदायिकता

2.3 संबंधित साहित्य :-

1. चीनारा बी, (1997). शिक्षा और जनतंत्र, नई दिल्ली.

यह पुस्तक जनतांत्रिक मूल्य से सम्बन्धित है। विद्यार्थियों को एन्स्ट्रक्शनल टेकनिक के द्वारा स्वतंत्रता स्वायतता, अपनी भव्यता के प्रति मान की ओर विषयाभिमुख करने के लिये वर्तमान शिक्षकों और भविष्य के शिक्षकों के आधारभूत सामग्री यह पुस्तक में हैं। जनतांत्रिक मूल्यों के सैद्धान्तिक सिद्धान्तों को इस विभाग में शामिल किया गया है। शिक्षा में जनतांत्रिक मूल्य की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में भी किताब में वर्णन है। रूपांतरित वेल्यू सर्वे कन्फ्रन्टेशन इंस्ट्रूमेन्ट और वेल्यू क्लेरिफाईग इंस्ट्रूमेन्ट हमको जनतंत्र मूल्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करता है और मूल्यों की उपयोगिता से अवगत कराता है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

2. गोस्वामी, पी.सी. (1987). जीवन, जनतंत्र और शिक्षा.

यह पुस्तक जीवन में जनतंत्र और शिक्षा से संबंधित है, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर पढ़ाने की पद्धति और शिक्षा की संरचना की चर्चा की गई है। जो महात्मा गांधीजी के मूलभूत शिक्षा के विचार पर आधारित है, उसमें जनतांत्रिक देश का आर्थिक विकास, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, शैक्षिक बेकारों की समस्या, राष्ट्रीय नीति और वैदिक युग में शिक्षा की प्रगति की बात की गई है।

3. झा, एस.एन. (1985). समाजवाद, असांप्रदायिकता और जनतंत्र, दिल्ली, अमर प्रकाशन.

शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य, समाजवाद, असाम्प्रदायिकता

और जनतंत्र के ध्येयों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। समाजवाद, असाम्प्रदायिकता और जनतंत्र को शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा हेतु कुछ मुख्य प्रयुक्तिओं के बारे में चर्चा की गई है। पुस्तक छः विभागों में विभाजित है। पुस्तक के दूसरे और तीसरे विभाग में भारत में वर्तमान समय में स्थापित शिक्षा प्रणाली और उसकी कमियों के बारे में दर्शाया गया है। चौथे विभाग में देश के सामाजिक, असाम्प्रदायिक और जनतंत्र के ध्येयों के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई है तथा पांचवे विभाग में शिक्षा के उपरोक्त ध्येयों को प्राप्त करने हेतु प्रयुक्तियों का वर्णन किया गया है। लेखक का मानना है कि "यह प्रयुक्तियों के द्वारा ही भारतीय संविधान के मुख्य आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है।"

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

4. **जोशी बी. आर. (1982). समानता की शोध में जनतंत्र,**

इस पुस्तक में उन समस्याओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत और अन्य जनतांत्रिक देशों का सामना करना पड़ता है। दलित, शोषित, पीड़ित और लघुमती की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है और उन्हें निम्न काम करने का स्त्रोत माना जाता है। जब यह लघुमती में समानता पाने की भावना जागृत होती है, तब वह अपने विशेषाधिकार और आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिये वह समाज को चुनौती देते हैं। समानता प्राप्त करना आधुनिक युग में बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है। फिर भी विश्व के देशों में समानता प्राप्ति की शोध ने मनुष्य में विसंवादिता, निराशा और हिंसा को जागृत किया है। भारत में भी समानता प्राप्ति के लिये बनाये गये नियमों से भी विसंवादिता, निराशा और हिंसा भड़की है। भारत में सामाजिक मूल्यों और आर्थिक संरचना को टिकाये रखके समानता की

प्राप्ति करना और वर्तमान सरकारी नीतियों के बारे में चर्चा की गई है। लघुमती को सरकारी नीतियों के द्वारा निश्चित रूप से राजकीय प्रवेश भी मिला है, जो कि समानता को बनाये रखने के लिये है, उसके बारे में भी इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है।

5. सिंघ एच. (1983). भारत में विद्यार्थियों का जनतांत्रिक विचार. नई दिल्ली.

विद्यार्थियों में अभिवृत्ति एवं विचारों का निर्माण करने में सामाजिक, राजकीय और आर्थिक कारकों की अगत्यता का इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इस अभ्यास के लिये बिहार के गया शहर के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के 600 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। मध्यमान प्रमाणित विचलन, टी-रेश्यो और प्रतिशत का उपयोग द्वारा पृथक्करण के लिये किया गयवा। जनतांत्रिक पद्धति के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति परीक्षण करने के लिये प्रश्नावली निर्माण की गई।

इस अभ्यास के निष्कर्ष यह है कि विद्यार्थी में राजकीय गुणों के प्रति दृष्टि, लघुमती मतभेद में सहिष्णुता और स्पर्धात्मक पक्ष पद्धति को उत्तेजन देने से संबंधित है। मूल्यों एवं लोक जनतांत्रिक संस्था का नयी पीढ़ी में सामाजीकरण करने में भारतीय जनतांत्रिक प्रणाली कितनी मदद रूप बन सकती है, उसके बारे में जनतंत्र की वैज्ञानिक पद्धति को विकसित करने में यह अभ्यास उपयोगी है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि जनतंत्र प्रणाली तब ही स्थायी रह सकती है जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को शासित करने का विश्वास संपादित करें और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ सके।

6. मोहन्ती जे. (1980). भारत में उड़ीसा के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा पर जनतंत्रात्मक का असर अप्रकाशित लघु-शोध प्रबन्ध, शिक्षा विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा, भारत.

यह वर्णनात्मक अनुसंधान में जनतंत्र के प्रति शिक्षक और निरीक्षक के विचारों की खोज निकालने का प्रयत्न किया गया है, और वो अपने कर्तव्यों के प्रति जनतंत्रात्मक के संदर्भ में कितने जागृत है, वह जानने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक शिक्षा पर जनतंत्र का असर और प्राथमिक शिक्षा का जनतांत्रिकीकरण करने में विघ्नरूप तत्वों को खोज निकालने का प्रयत्न किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं को इस अभ्यास में शामिल किया गया है। प्रश्नावली के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया गया और प्राथमिक शिक्षा के जनतांत्रिकीकरण तत्वों को खोजा गया है।

Regional Institute of Education LIBRARY

7. जोशी, एस. (1998). माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र में मूल्य पृथक्करण पुयक्ति द्वारा लोकशाही मूल्यों का विकास, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध शिक्षा विभाग, दिल्ली, अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

नागरिकशास्त्र की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में जनतंत्र मूल्यों का विकास और मूल्य पृथक्करण प्रयुक्त का असर का अभ्यास करना यह अभ्यास के उद्देश्य थे और अलग-अलग समूहों में अलग-अलग मात्रा में जनतांत्रिक मूल्यों के विभाग का अध्ययन किया गया है। अभ्यास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संशोधक ने 21 शून्य परिकल्पना का उपयोग किया है। जनतंत्र के मूल्यों के विकास के लिये समय श्रेणी

डिजाईन और वर्णनात्मक एप्रोच का सहारा लिया गया है। नागरिकशास्त्र के अध्यापन से विद्यार्थियों में जनतांत्रिक मूल्यों, विकास में मूल्य पृथक्करण प्रयुक्त को असरकारक माना गया है।

8. **देवी एन.के. (1994). गाँधी और जनतंत्र अप्रकाशित शोध प्रबन्ध (पोलिटिकल साईन्स), मणीपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल, भारत.**

इस अभ्यास में पांच प्रकरण हैं। विद्वानों ने सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर गांधीजी के विचारों को प्रदर्शित किया है। प्रथम प्रकरण जनतंत्र का विचार और उसके बारे में गांधीजी के विचारों को प्रदर्शित किया है। दूसरे प्रकरण में गांधीजी के स्वतंत्रता अधिकारी व समानता और मूल्यों के विचारों के बारे में चर्चा की गई। तीसरे प्रकरण में पंचायत प्रणाली पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में गांधीजी के विचारों की चर्चा की गई। भारत देश को जनतंत्र में समृद्धि प्रदान करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। इस विचार पर गांधीजी की मान्यता की चर्चा प्रकरण चार में की गई है। अंतिम प्रकरण में गांधीजी की जनतंत्र के बारे में विचार को सारांशित किया गया है।

9. **वोवेल, वी.आर. (1993). जनतंत्र के पीछे, जनतंत्र से लेकर नागकिताशाही तक, पुणे, बेल पब्लिकेशन.**

इस पुस्तक में नागरिकताशाही के सिद्धान्तों, लाभालाभ व जनतंत्र की मर्याओं की चर्चा की गई। इस पुस्तक में जनतंत्र की कोई भी मर्यादाओं का समाधान दिया गया है। अर्थशास्त्र, राजकारण व समाज की कोई भी समस्याओं का निराकरण इस पुस्तक में दिया गया है। श्रम के क्षेत्र में

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

न्याय, समानता और अच्छी विवेक बुद्धि का फैलाव करने वाले कारकों के बारे में भी चर्चा की गई है। यह ब्लेक-बेन्ड संस्कृति और नो-स्ट्राईक की सिफारिश करता है। नागरिकताशाही का नया दर्शन न सिर्फ मानवता और विश्व को विनाश से बचाने का औषध है, परन्तु इस नर्क जैसे विश्व में स्वर्ग का निर्माण करता है। भारत में आधुनिक जनतंत्र के विकास से संबंधित कुछ मुद्दों का भी वर्णन किया गया है।

10. **द्वापर, ऐ.जे. (1988). जनतंत्र के लिये प्रौढ़ शिक्षा : एस.सी. दत्ता के विचार, भारत (जर्नल ऑफ एडल्ट एजूकेशनल) 49(1)38-42.**

लेखक ने प्रौढ़ शिक्षा पर एस.सी. दत्ता के विचारों पर प्रकाश डाला है। दत्ता का मानना है कि जनतंत्र में नई व्यवस्था लाने के लिये प्रौढ़ शिक्षा, पूर्व चित्रण बनता है कि जहाँ सभी को समानता, सामाजिकता एवं आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर प्रदान करता है। जनतंत्र में जनता का सहयोग सुनिश्चित है। जनता के सहयोग में लापरवाही कमी को दूर करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा मुख्य भूमिका निभाती है। सार्वजनिक कार्यो के लिये जनता में व्यक्तिगत जागरूकता लाने के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जनतंत्र फैलाव के लिये प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

11. **मुथैया बी.सी. एवं रंगाचार्यला एस.वी. (1981). जनतंत्र पर मंतव्य और जनता में विश्वास के बीच सम्बन्ध (इंडियन साईकोलोजिकल एबस्ट्रेक्टस) 18 (1) 47.**

इस अभ्यास में जनता में विश्वास और जनतंत्र पर मंतव्य के बीच सम्बन्ध का अध्ययन किया गया है। हैदराबाद के अलग-अलग कार्यालयों

में से 244 कार्यालयों का इस अभ्यास के लिये चुना गया है। जनता विश्वास स्केल का उपयोग उनके बीच में स्थित सम्बन्धों को खोज निकालने के लिये किया गया। अभ्यास से यह पाया गया कि जनता में विश्वास, जनतंत्र में धानात्मक मत से जुड़ा हुआ है। कर्मचारियों एवं व्यावसायिक के जनतंत्र में जनता में विश्वास के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

12. **जनतंत्र संचालन क्षमता के विकास के लिये नैतिकता और एकीकरण (जर्नल ऑफ ह्यूमन वेल्यूस) 5 (2) 125-133.**

नैतिकता और एकीकरण में सुधार के बीच सम्बन्धों का यहाँ अभ्यास किया गया है। नैतिकता, सांस्कृतिक निश्चय जैसे कि मूल्यों, अभिवृत्ति, वर्तन आदि का समूह है। जहाँ एकीकरण, वैयक्तिक और जनतंत्र नीति की सामाजिक मूर्तस्वरूप है। जनतंत्र का संवर्धन करने और जनतंत्र के फैलाव के लिये नीति और एकीकरण में सुधार लाना आवश्यक है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदारिता होती है। नैतिकता में एकीकरण में सुधार हेतु और बढ़ावा देने के लिये पारदर्शिता और जबावदारिता के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने पर महत्व दिया जाना चाहिए। तब ही हम 21वीं सदी की चुनौती का सामना कर सकते हैं।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

13. **रत्न ऐ. (1988). गांधी जी के जनतंत्र प्रारूप की सर्म्पकता, गांधी मार्ग, 10 (1) 28-42.**

प्रस्तुत लेख में गांधीजी के जनतंत्र प्रारूप के सम्पर्कता के ऊपर प्रकाश डाला गया है। पश्चिमी जनतंत्र के आलौचक गांधीजी ने कहा है

कि भारत को सच्ची जनतंत्र विकसित करने हेतु प्रयास करना चाहिये, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बन्धुता सच्चे अर्थ में प्राप्त हो। उन्होंने सही अर्थ में जनतंत्र के विकास के लिये सत्याग्रह, ग्रामोद्योग, मूलभूत शिक्षा, अस्पृश्ता निवारण, लोंगों में संवादिता और अहिंसा को अपनाने की बात की। गांधी जी चाहते थे कि मंत्रियों, केबीनेट मंत्रियों और पब्लिक सर्वेन्ट्स को सादा जीवन जीना चाहिये। लेखक के मतानुसार, गांधी जी का जनतंत्र का प्रारूप न केवल अपने देश के लिये परन्तु अन्य देशों के लिये भी उतना ही समर्पक है।

14. रूहेला एस.पी. (1988). भारत में शिक्षा का जनतांत्रिकीकरण, यूनिवर्सिटी न्यूज, 26 (12) 5-9.

इस बात पर भार दिया गया है कि जनतंत्र दो मूलभूत मूल्यों पर आधारित है समानता और स्वतंत्रता। हमारी शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित समस्याओं की यहाँ सविस्तार चर्चा की गई है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) के लक्षणों को दर्शाया गया है और उसकी विवेचना की गई। लेखक का मानना है कि समाज में व्याप्त दूषणों की जड़ में मूल्यों के प्रति जागरूकता का अभाव और मूल्यों का आधुनिक समाज में नष्ट होना मुख्य है। हमारे देश में शिक्षा के जनतांत्रिकीकरण का आदर्श चित्र बनाने के लिये भाषा और कार्य के बीच में संवादिता बनाये रखने की बात करते हैं।

2.4 उपसंहार

उपरोक्त अध्ययनों का अध्ययन करने से पता चलता है कि मूल्यों के अध्ययन के क्षेत्र में अधिक शोध नहीं हुए हैं। विभिन्न स्तर के विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षकों का जनतंत्रात्मक मूल्यों के प्रति अध्ययन किसी शोधकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। जो भी अध्ययन कार्य हुए है वे शिक्षकों के मूल्य से प्रत्यक्ष रूप से आधारित नहीं है।

अतः उपरोक्त शोधों को प्रस्तुत शोधकार्य हेतु आधार बनाया है।